



# यीडा में खुलेंगे रोजगार के नए दरवाजे

प्राधिकरण औद्योगिक कलस्टर की तीन योजनाएं आज करेगा लांच

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● 10 लाख से अधिक को मिलेगा रोजगार

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा आज औद्योगिक कलस्टर की तीन योजनाएं लांच करेगा। अपैरल, एमएसएमई व हैंडीकॉफ्ट कलस्टर की इस योजना में करीब एक हजार भूखंड होंगे। इसमें 250 मीटर से लेकर 40 हजार वर्ग मीटर तक के भूखंड शामिल होंगे। एमएसएमई के लिए 514, हैंडीकॉफ्ट के लिए 203 और अपैरल पार्क के लिए 213 भूखंड इस योजना में होंगे। चार हजार मीटर से कम आकार के भूखंडों का डॉ निकला जाएगा इसके बड़े भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के जरिये किया जाएगा।

यमुना प्राधिकरण अपैरल, एमएसएमई माइक्रो, स्पाल एंड मीडिम इंडस्ट्री व हैंडीकॉफ्ट कलस्टर की औद्योगिक योजना लांच करेगा। यह योजना 26 जनवरी को आयोजित आवेदन पहली फरवरी से स्वीकार किए जाएंगे। इस योजना में 31 मार्च तक आवेदन किए

## कई बड़ी कंपनियों को मिल चुके हैं भूखंड

निवेश समिति से यमुना प्राधिकरण की ओर उद्यमियों का रुझान बढ़ा है। यहां बीची जैसी बड़ी कंपनियों ने जमीन आवंटन कराया है। अब तक करीब 188 इकाइयों के लिए आवंटन किया जा चुका है। इसके अलावा बड़ी कंपनी, बीकानेर, रेमसंस समेत दर्जनों चीन कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों को जमीन आवंटित कर दी गई है। इन सभी कंपनियों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन बड़ी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिले, इसके भी इंतजाम यमुना प्राधिकरण ने किए हैं।

स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार : तीनों कलस्टर में 50 हजार करोड़ का निवेश होगा। प्राधिकरण के नियमों के मुआविक इसमें स्थानीय युवाओं के लिए कोटा तरह किया जाएगा ताकि यहां के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। औद्योगिक के तीन कलस्टर की योजना 26 जनवरी को लांच की जाएगी।

-डॉ अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

बाबा है कि तय समय पर डॉ निकालकर आवंटियों को कब्जा दे दिया जाएगा।

प्राधिकरण सेक्टर-29 में तीनों कलस्टर की योजना बनाई है। इसके लिए करीब 380 हेक्टेयर जमीन एवं करोड़ 100 लौंगल कर दिया जाएगा। यहां योजना में देश के किसी प्रदेश का निवासी आवेदन कर सकता है। इसमें अंतलाइन आवेदन निवेश मित्र एवं के जरिये होंगे। प्राधिकरण का

जमीन पर प्राधिकरण का कब्जा है। अफ सों को कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो जमीन और बड़ा दी जाएगी। इन कलस्टर में से दो एक जिला एक उत्पाद के तहत आते हैं। ये थाने मंगलवार से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि ये थाने लोगों को सुविधा और अपराध पर काबू पाने के लिए बनाए गए हैं। अधिकतर

ट्रांस हिंडन को मिले दो नए थाने, मंगलवार से होगा काम शुरू

गाजियाबाद। जनपद के हिंडन पार क्षेत्र में दो नए थाने 28 जनवरी से काम करना शुरू कर देंगे। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने दोनों थानों में प्रभारी निरीक्षकों की तैयाती के लिए देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें टीला मोड़ थाना का प्रभारी रण सिंह और कौशांबी थाना का प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी अजय कुमार को बताया गया है।

बता दें कि यहां थाना बनाने की मंग सालों से हो रही थी। एसएसपी ने बताया कि टीला मोड़ और कौशांबी में दो नए थाने साहियाबाद और ईंदियापास थाने की अनुमति पुलिस अधीक्षक (शहर) मरीच मित्रों को इन थानों की स्थापना के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये थाने मंगलवार से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि ये थाने लोगों को सुविधा और अपराध पर काबू पाने के लिए बनाए गए हैं।



गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमग नोएडा का प्रवेश द्वार।

फोटो : दीपक यादव

# मतदाता दिवस के अवसर पर निकाली जागरूकता रैली

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● कई विषयों पर प्रतियोगिता भी हुई

जिला प्रशासन एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जागरूकता अधियान का आयोजन किया गया। एप्रेल और डिसेम्बर निर्माण के साथ ही हिस्सा विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। छात्रों के लिए स्कृप्टिंग का माध्यम से छात्रों ने आयोजित किया गया।

पोर्टर के माध्यम से छात्रों ने लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। बताया कि अप्रेल अधिकार का प्रयोग करें और मतदाता दिवस के लिए योजना बनाएं। यह योजना में देश के किसी प्रदेश का निवासी आवेदन कर सकता है। इसमें अंतलाइन आवेदन निवेश मित्र एवं के जरिये होंगे। प्राधिकरण का



प्रेसवार्ता को संबोधित करते भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बोडे सदस्य विमल।

# जीडीए के 70 करोड़ के टेंडर पर उठाए सवाल

पार्षद ने कहा-जनता के पैसे का दुरुपयोग बर्दाशत नहीं करेंगे

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

भाजपा के वरिष्ठ पार्षद ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से इंटरेग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के लिए निकाले गए 70 करोड़ के टेंडर को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिया है।

पार्षद ने इस पत्र के माध्यम से एक प्रेसवार्ता के द्वारा मिडिया को भी जारी किया। उनके साथ जीडीए बोर्ड को प्रयोग करने के लिए यहां पर करोड़ 1 की रुपीय विमल ने कहा है कि यह एक नियम बनाने के लिए उत्तर दिल्ली के लिए भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि यह एक नियम बनाना जल्दी करना चाहिए।

पार्षद का आरोप है कि जीडीए ने जिला 112 चौराहों पर ट्रैफिक सिस्टम की मोटी रकम बर्बाद करने का एक प्रयोग करने के लिए यहां पर विमल ने यहां पर एक नियम बनाया है। उन्होंने बताया कि यह एक नियम बनाना जल्दी करना चाहिए।

पार्षद को इन नियमों के लिए उत्तर दिल्ली के लिए भूमिका नहीं है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है। उन्होंने बताया कि यह एक नियम बनाना जल्दी करना चाहिए।

पार्षद ने इस पत्र के माध्यम से एक नियम बनाया है। उन्होंने बताया कि यह एक नियम बनाना जल्दी करना चाहिए।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।

उत्तर दिल्ली के लिए यहां पर एक नियम बनाया है।



# केरल की तर्ज पर हरियाणा में मिलेगी शिक्षा एवं स्वास्थ्य को रफ्तार

मलिक असगर हाशमी। चंडीगढ़



सोमा त्रिपाठी, विधायक बड़खल



केके शैलजा, स्वास्थ्य मंत्री केरल

केरल सरकार से सीधे लेकर हरियाणा सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत न केवल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जाएंगी, बल्कि केंद्र के बेटी चबाओं, बेटी पढ़ाओं का कार्यक्रम को सुधारी में रफ्तार देने में भी मदद मिलेगी।

योजना को आगे बढ़ाने के लिए फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीमा त्रिपाठी की अध्यक्षता में विधायकों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य कमेटी बहाल में केरल के राजधानी विराटनगरपुरम् पर से लौटी है। इस कमेटी में नंदगी युगा, रामकुमार गौतम, राजेंद्र जून, विवेद भयाना और बलबीर वालींकी शामिल थे। कमेटी के सदस्य पांच दिनों तक केरल

में

केरल सरकार के मेहमान रहे। लौटने के बाद वहां सीधे गए गुरु अधिकारियों से साझा किए जाएंगे, ताकि खट्टर सरकार को ठोस योजना सौंपी जा सके। कमेटी के ठोस योजना की शिक्षा एवं स्वास्थ्य कमेटी बहाल में केरल के राजधानी विराटनगरपुरम् पर से लौटी है। इस कमेटी में नंदगी युगा, रामकुमार गौतम, राजेंद्र जून, विवेद भयाना और बलबीर वालींकी शामिल थे। कमेटी के सदस्य पांच दिनों तक केरल

कुछ और दिख सकते हैं बदलाव

विधायकों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य कमेटी के सुझाव मान लिए गए तो केरल की तर्ज पर आगे बाले समय में हरियाणा में कुछ और बदलाव दिख सकते हैं। केरल में विधायकों की एक जल संसाधन कमेटी है। इसकी मदद से सरकार यानी को लेकर काफी काम कर रही है। इसकी परिणाम है कि वहां जल संकट जैसी समस्या नहीं है। केंद्र सरकार ने भी जल के महत्व को समझते हुए यानी का अलग से मंत्रालय बनाया है। त्रिपाठी ने केरल से लौटने के बाद ऐसा ही सुझाव विधायक संघके समस्या पर्याप्त संकेत। सुझाव में कहा गया है कि अपने प्रदेश में अभी विधायकों को करीब आठ कमेटीय हैं। यहां भी एक पर्यावरण एवं जल संसाधन कमेटी का गठन किया जाए। इसके अलावा त्रिपाठी ने नगर विकास मंत्री अनिल विज से मिलकर कुछ और सुझाव दिए हैं। मसलन सङ्केत पर प्लास्टिक के बोतल क्रश करने की मशाने लाई जाए। ल्यास्टिक को डी-कॉपरेट कर दाना तो सङ्केत के मिर्जाम में उत्तरोग में लाया जा सके। सरकार यह व्यवस्था पीछे पर भी कर सकती है या कुछ लोगों को डीसी रेपर पर खड़क भी कराया जा सकता है।

दस हजार करोड़ रुपये काने का सरकार का इरादा है। मगर इस पैसे में आगे बढ़ते हुए हरियाणा में अगले महीने विधानसभा में पेश होने वाले बजट में इसे पांच हजार से बढ़ाकर भी कराया जा सकता है।

बखूबी पहुंच सके। इसे टॉलोने के लिए ही विधायकों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य कमेटी केरल प्रभाग पर ताकि आमजन तक स्वास्थ्य सेवाएं गईं।

पानी को लेकर खट्टर सरकार गंभीर

जल संरक्षण को लेकर खट्टर सरकार बेहद गंभीर है। पानी को बचाने के लिए ही प्रदेश में सत जिलों में धन की खेती पर पांच लाख दी गई है। योगी त्रिपाठी ने केरल से लौटने के बहुत कुछ नहीं है। मौजूदा लिंगानुपात 952 के असापास है। 2011 की जनगणना के समय यह अनुपात प्रति एक हजार लड़कों पर बचाने में एक बड़े लैंड रिपोर्ट के बचाने की संख्या 877 थी। इसकी मदद से खेतों की उत्तरा क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है, जो बक्तव्य की महत्वपूर्ण मार्ग है।

केरल में भाजपा की धूरविराजी वाम दल की सरकार है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार वहां की स्वास्थ्य सेवाएं लिंगानुपात और बढ़ाने में भी खास दिलचस्पी नहीं है। हरियाणा के लोग लड़कियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने का नीति जारी है कि केरल की तमाम प्रधानों का नीति जारी है।

शिक्षा के स्तर से बेहद प्रभावित है। सीमा त्रिपाठी ने केरल का अभी लिंगानुपात एक हजार लड़कों पर 1084 महिलाएं हैं। इस हिसाब से इसके केरल सरकार की मदद ली जा रही है। केरल भ्रमण के दौरान वहां की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कमेटी की काफी सहायता की।

सीमा त्रिपाठी की मार्ग से पानी को लेकर खट्टर सरकार बेहद गंभीर है। मौजूदा लिंगानुपात 952 के असापास है। 2011 की जनगणना के समय यह अनुपात प्रति एक हजार लड़कों पर बचाने के लिए लड़कियों की संख्या 877 थी। इसकी मदद से खेतों की उत्तरा क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है, जो बक्तव्य की महत्वपूर्ण मार्ग है।

## संक्षिप्त-समाचार

निरंकारी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जीते आठ पदक



सोहना। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय युवा उत्सव 2020 में एनबीजीएसएप कॉलेज के विद्यार्थियों ने अला-अलग प्रतियोगिताओं में आठ पदक जीते। डेक्लामिशन में मनीषा ने पहला स्थान प्राप्त किया। उर्दू कविता पाठ अंतर्राष्ट्रीय अला-युसफ, खालिद के वाटर टैंक से पानी की महिलाओं को बाटर टैंक से बाटी पहुंच पाई। इसकी मदद से खेतों की संख्या जारी है। योगी त्रिपाठी की शिक्षा एवं स्वास्थ्य कमेटी केरल प्रभाग पर ताकि आमजन तक स्वास्थ्य सेवाएं गईं।

तक नहीं पहुंच पा रहा है। वर्तीं टूरिया मोहल्ले में बने बाटर टैंक की बिजली की मोहर एक साथ से खारब पड़ी है। नतीजनान, बाटर टैंक से पानी की सासांगी ग्रामीणों को नहीं पहुंच पा रही है। मजबूरी में गांव की महिलाओं को बाटर टैंक से पानी लाना पड़ रहा है। नतीजनान, बाटर टैंक से पानी की सासांगी ग्रामीणों को नहीं पहुंच पा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलालों के विधायक सुधीर सिंगला, बादशहपुर के विधायक रामेश दीलाताबाद, हरियाणा विधानसभा के पूर्व टिप्पणी स्थानीय गोपींवंश गहलोत, कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा की पत्नी उमा सुधा, भाजपा जिला अध्यक्ष धूपेन्द्र चौहान, मंडलायुक अशोक सांगवान, पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल, उपायुक्त अमित खन्नी, अवैद कैलांडर के विधायक संसाधनों जैसी होगी। इसके लिए उन्होंने सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थाएं मिलकर प्रदेश में शिक्षा के स्तर में निर्देश दे रखे हैं कि वे प्राइवेट स्कूलों की मैनेजरें से साथ एमओयू सँझने में सुधार लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अवसर के बाद अधिकारियों ने यहां खेतों को नहीं लाया जा सकता।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों के सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन आश्रसन के ग्रामीणों में रोध बना हुआ है।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों को सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन आश्रसन के ग्रामीणों में रोध बना हुआ है।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों को सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन आश्रसन के ग्रामीणों में रोध बना हुआ है।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों को सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन आश्रसन के ग्रामीणों में रोध बना हुआ है।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों को सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन आश्रसन के ग्रामीणों में रोध बना हुआ है।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों को सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन आश्रसन के ग्रामीणों में रोध बना हुआ है।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों को सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन आश्रसन के ग्रामीणों में रोध बना हुआ है।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों को सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन आश्रसन के ग्रामीणों में रोध बना हुआ है।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों को सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन आश्रसन के ग्रामीणों में रोध बना हुआ है।

गांव की अबादी छह हजार से भी ज्यादा है। बताया गया है कि गांव के योगी देवों को सालाना करोड़ रुपये दे रहे हैं। आरोप है कि मुख्य राष्ट्रीय अधिकारियों को कहा गया है, ल



# जीएसटी प्रणाली में दोष निवारण की अनिवार्यता

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत संग्रह के उमीद से कम होने एवं परिणामतः जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के अंतर्गत राज्यों को क्षतिपूर्ति के अपने बाद पूरे करने में केंद्र सरकार की असमर्थता की पृथक्खमि में (इसके अंतर्गत पांच वर्ष के लिए मुआजा दिया जाना है अर्थात् 2021-22 तक जिसको गणना वास्तविक संग्रहण एवं 2015-16 के स्तर पर चार प्रतिशत की वृद्धि के द्वारा राजस्व के अंतर के तौर पर की जानी है), जीएसटी परिषद वर्तमान दर संरचना एवं क्रियान्वयन व्यवस्था का समग्र पुनरावलोकन कर रही है।

**उत्तम गुप्ता**  
(लेखक नीति विश्लेषक एवं सम्पादक हैं)

## वस्तु

एवं सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत संग्रह के उमीद से कम होने एवं परिणामतः जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के अंतर्गत राज्यों को क्षतिपूर्ति के अपने बाद पूरे करने में केंद्र सरकार की असमर्थता की पृथक्खमि में (इसके अंतर्गत पांच वर्ष के लिए मुआजा दिया जाना है अर्थात् 2021-22 तक जिसको गणना वास्तविक संग्रहण एवं 2015-16 के स्तर पर चार प्रतिशत की वृद्धि के द्वारा राजस्व के अंतर के तौर पर की जानी है), जीएसटी परिषद वर्तमान दर संरचना एवं क्रियान्वयन व्यवस्था का समग्र पुनरावलोकन कर रही है।

इस बीच, जीएसटी परिषद एवं जी विवादास्पद मुद्दा आया है जिस पर तात्पालिक रूप से अध्यात्म देने की आवश्यकता होनी वह एकत्रित अगत कर क्रेडिट के उपचार से संबंधित है जो निर्गत कर देयता के विरुद्ध स्वतः समाज नहीं होगा। जीएसटी छांचे के मूल में है वह लकड़ा जो किसी उत्पादक-आपूर्तिकर्ता को मूल त्रिभवन के समक्ष अगत पर चुकाए गए गर के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है। यह कर पर कर के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने में मददगार होता है और उत्पाद के लिए उत्पाद की कीमत घटा देता है, जबकि पूर्वोक्त मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय वस्तु कर एवं कई अन्य स्थानीय शुल्क उस भीषण प्रभाव के पर्याय हुआ करते थे।

समस्याजनक स्थिति पैदा हो सकती है यदि उत्पादक/आपूर्तिकर्ता पर अगत खरीद पर संग्रहीत क्रेडिट को नियातिर करने के लिए संबंधित अगत कर देयता के मूल वस्तुओं को उसी समस्या का समाप्त करना एवं रहा है। उद्दोने अवसंचना को संबंधित करने के लिए भारी निवेदन किए हैं जबकि उनके राजस्व में नीत्री गिरावट आई है, टैरिफ के रिकार्ड निम्न स्तर पर जाने की बढ़ीलत और ऐसा 2016 में रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद आया है।

इससे उनके अगत खरीदों पर एकत्र क्रेडिट को बढ़ा दिया और, प्राथमिक रूप से निम्न टैरिफ टिक्की कीपत के कारण, सरकार को होने वाले उनके जीएसटी भुगतान घटा दिए, इस तरह देयताओं के स्वतः नियातिर करने के बाद अगत खरीद पर एकत्र क्रेडिट को बढ़ा दिया और अधिकतम रूप से अविवादित वस्तुओं को लगातार नियातिर करने के लिए संबंधित अगत कर देयता के मूल वस्तुओं को उसी समस्या का समाप्त करना एवं रहा है। उद्दोने अवसंचना को संबंधित करने के लिए भारी निवेदन किए हैं जबकि उनके राजस्व में नीत्री गिरावट आई है, टैरिफ के रिकार्ड निम्न स्तर पर जाने की बढ़ीलत और ऐसा 2016 में रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद आया है।

समस्याजनक अपनी अपेक्षा अगत खरीद पर संग्रहीत क्रेडिट को नियातिर करने के लिए अपनी अपेक्षा अगत कर देयता के मूल वस्तुओं को उसी समस्या का समाप्त करना एवं रहा है। उद्दोने अवसंचना को संबंधित करने के लिए भारी निवेदन किए हैं जबकि उनके राजस्व में नीत्री गिरावट आई है, टैरिफ के रिकार्ड निम्न स्तर पर जाने की बढ़ीलत और ऐसा 2016 में रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद आया है।













# राजपत्र

जब भयावह व बर्बर  
कानूनों की बात आती है  
तो देश की आत्मा कांप  
उठती है कि 2012 में  
निर्भया मामले से लेकर  
2019 में हैदराबाद में 26  
वर्षीया डाक्टर के  
बलात्कार व हत्या तक,  
कुछ भी नहीं बदला है।  
अपराध कानून में  
संशोधनों के बावजूद  
क्यों किसी भी प्रकार की  
राहत नहीं है, इस संबंध  
में कुछ कड़वी सच्चाइयों  
को सामने लाती  
मुख्या हाशमी की रिपोर्ट

# ਖ਼ਾਨ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰ



**16** दिसंबर, 2012, वो तारीख है जिसे भारत निकट भविष्य में तो भूलने वाला नहीं है। वो एक सर्द रात थी और अधिकांश दलिलीवासी अपने घरों में कंबल ओढ़े टीवी पर दिन भर की खबरें सुन रहे थे। कहीं पर, 23 वर्षीया फर्जियोथेरेपी इंटर्न सड़क पर निर्वस्त्र पड़ी हुई थी उसके गुणांग रक्तरंजित तथा आतें बाहर निकली हुई थीं। उसे एक राहगीर ने मरणासन्न हालत में पाया था। उस रात ने देश को, खासतौर पर राजधानी को झकझोरा दिया। लड़की निडर थी, इसलिए मीडिया द्वारा उसे प्रदान किए गए नाम, निर्भया को न्याय देने की मांग करते हुए देश भर में कैंडल लाइट प्रदर्शन हुए। 29 दिसंबर को, सिंगापुर अस्पताल में निर्भया की मौत हो गयी। उसके अंतिम शब्द थे: “माँ, मैं जीना चाहती हूँ।”

हूँ। साल 2020 में आते हैं। सात से अधिक वर्ष बीतने के बाद, हाई कोर्ट ने चार आरोपियों को सजा सुनाई- पवन गुप्ता, अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और मुकेश सिंह को फांसी की सजा सुनाई गयी। हालांकि फांसी देने की तारीख 22 जनवरी, 2020 को सुबह 7 बजे घोषित की गयी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अब फांसी की तारीख 1 फरवरी, 2020 की सुबह 6 बजे निर्धारित कर दी गयी है। ऐसा मुकेश द्वारा दायर की गयी दया याचिका को राष्ट्रपति राम नाथ

- फरवरी में, बिहार की एक 19 वर्षीय लड़की के साथ उसके पिता के सामने छह लोगों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।
- मार्च में, मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक 12 वर्ष की दलित लड़की का उसके चाचा और उसके तीन भाइयों द्वारा बलात्कार किया गया विसिर काटकर हत्या कर दी गयी।
- मार्च में, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 16 साल की लड़की को, जब वह शौच के लिए गयी हुई थी आगोपी के घर बेहेशी की हालत में पाया गया।
- अप्रैल में, दिल्ली एवं गुरुग्राम में एक



— 2 —

लगभग 23 किमी दूर दक्षिण में एक अंडरपार के करीब बर्बतापूर्वक जली हुई उसकी लाश पाई गयी।

पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया-  
लड़की के मोबाइल फोन से तथा सीसीटीवी  
कैमरों में प्राप्त सुबूत के आधार पर मोहम्मद  
आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन कुमार व  
चिंताकुंटा चेना केशवलू को पकड़ा गया। पुलि-

ने 24 घंटे के भीतर मामला सुलझा दिया और सभी चारों आरोपियों को गोली मार दी गयी। कठुआ, जम्मू-कश्मीर के करीब रसाना गांव की एक आठ वर्षीय लड़की को उठा लिया गया उसका सामूहिक बलात्कार तथा हत्या कर दी गयी। लड़की का 10 जनवरी, 2018 को अपहरण किया गया और उसकी लाश सात दिन के बाद मिली। घटना में सांझी राम को मुख्य आरोपी पाया गया। वह पारिवारिक मंदिर का पुजारी था जहां घटना को कथित तौर पर अंजाम दिया गया। उसका बेटा विशाल और भतीजा, नाबालिग, को भी मामले में दोषी पाया गया। अन्य लोग, जिन्हें दोषी पाया गया हैं, वे हैं दीपक खजुरिया और प्रवेश कुमार, जो पुलिस अधिकारी हैं।

है, तिलक राज, हड्ड कास्टबल और अरावद दत्त सब इंसपेक्टर।

10 जून, 2019 को, सात में से छह आरोपियों को दोषी पाया गया, तथा साँझी राम का बैटा, विशाल को सुबूतों के अभाव के कारण

प्रति बरी कर दिया गया। सांझी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को, एक लाख रुपए के जुर्मनी के साथ, 25 साल के आजीवन कारावास की हैं और फिर पूरा मामला बिना किसी समाधान के, जिसके लिए भाषण दिया गया था, अन्य हजारों मामलों के नीचे ढब जाता है।

सजा सुनाइ गयी। अन्य तीन आरोपी- तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेन्द्र वर्मा को मामले में महत्वपूर्ण सुबूत मिटाने के जुर्म में पांच साल जेल की सजा सुनाई गयी। आठवें आरोपी, सांझी राम के नाबालिंग भट्टीजे, पर किशोर अदालत में

मुकदमा चलाया गया।  
एक और भयावह घटना, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था, वो है उन्नाव बलात्कार की। 4 जून, 2017 को, एक 17 वर्षीय लड़की का उत्तर प्रदेश विधायक, कुलदीप सेंगर तथा उसके भाई व सहयोगियों द्वारा गेंगरेप किया गया। 16 दिसंबर, 2019 को सेंगर को बलात्कार का बात नहीं सुनता है। यह सरकार का दायित्व है कि वो देखें कि क्यों बलात्कार बढ़ रहे हैं और अपराधियों को क्यों कोई डर नहीं है। सरकार को ऐसे मामलों में जवाबदेह होना चाहिए।”  
सात साल पहले, जब निर्भया की निर्मम हत्या की गयी थी, तो नए नियमों व प्रवधानों तथा मौजदा कानूनों के संशोधन संबंधी काफी

तथा भाजूदा कानूनों के सशावेत सभवों काफी चर्चा सामने आयी थी लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ या नहीं बदला। कटुआ बलात्कार मामले के बाद, आपराधिक कानून संस्थोधन अधिनियम, 2018 लागू किया गया जो कहता है कि दोषी को 12 साल से कम उम्र की

बचान के बार म बात कर रह ह, लाकन  
असलियत में कोई भी कुछ ठोस नहीं कर रहा  
है। निर्भया के माता पिता या इस संदर्भ में आम  
आदमी के रूप में, इंसान केवल अपनी राय ही दे  
सकता है। मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों से  
सवाल पूछना चाहिए कि वे हमारी लड़कियों की  
सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं।” वह बताते हैं  
कि लोग आते हैं और कुछ दिनों तक भाषण देते

ह एक दाखा का 12 साल स कम उम्र का  
लड़की का बलात्कार करने पर फँसी की सजा  
जैसी अधिकतम सजा दी जा सकती है।  
हालांकि अधिकतम सजा बीस वर्षों की सजा  
है जो पहले दस साल तक की है।

---

>> पेज 3

.....

साल 2019 का खौफ नाक चेहरा

- फरवरी में, बिहार की एक 19 वर्षीय लड़की के साथ उसके पिता के सामने छह लोगों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।
  - मार्च में, मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक 12 वर्षीय की दलित लड़की का उसके चाचा और उसके तीन भाइयों द्वारा बलात्कार किया गया व सिर काटकर हत्या कर दी गयी।
  - मार्च में, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 16 साल की लड़की को, जब वह शौच के लिए गयी हुई थी, आरोपी के घर बेहोशी की हालत में पाया गया।
  - अपैट में, निर्मला संदीप में पांच साल की लड़की का बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गयी।
  - मई में, बिकानेर में एक विवाहित महिला के साथ तीन लोगों द्वारा गैंगरेप किया गया, जब वह लकड़ियां बीनने गयी थी।
  - मई में, पंजाब में एक ग्राइवेट स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया।
  - मई में, 17 साल की एक मूकबधिर लड़की का रामपुर में तीन लोगों द्वारा बलात्कार किया गया और दुष्कृत्य का वीडियो भी बनाया गया।
  - मई में, बांदीपुरा, जम्मू-कश्मीर में सातवां देरीपुरा विहंग में पांच



■ निकली थी।  
■ जून में, अलीगढ़ में दस रुपए देरे

- की बच्ची को एकांत जगह पर ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया।
  - जून में, आंध्रप्रदेश में एक 16 साल की लड़की के साथ पांच दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया।
  - जून में, उनाव में एक 11 साल की लड़की का बलात्कार करके हत्या कर दी गयी, उसकी लाश एक बगीचे से पड़ी पाई गयी।
  - जून में, देहरादून में एक 11 साल के लड़के द्वारा तीन साल की बच्ची का उस समय बलात्कार किया गया। जब बच्ची के माता पिता घर पर नहीं थे।
  - यहां में आठ लांसा में से 12





